



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022021-225436
CG-DL-E-24022021-225436

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 2021/फाल्गुन 5, 1942

No. 67]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 2021/PHALGUNA 5, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2021

मामला सं. एडी-ओआई-46/2020

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “पॉलीयुरेथेन लेदर है जिसमें पॉलीयुरेथेन के साथ एकतरफा या दो तरफा कोटिड किसी भी प्रकार का टेक्सटाइल्स शामिल होता है” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 6/55/2020—डी जी टी आर.—मेसर्स टॉपलाइन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये “पॉलीयुरेथेन लेदर है जिसमें पॉलीयुरेथेन के साथ एकतरफा या दो तरफा कोटिड किसी भी प्रकार का टेक्सटाइल्स शामिल होता है” (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत की मांग करते हुए एक आवेदन (जिसे यहां आगे “याचिका” भी कहा गया है) दायर किया है।

2. आवेदक ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति का आरोप लगाया है और यह अनुरोध किया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाये।

विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "पॉलीयुरेथेन लेदर है जिसमें पॉलीयुरेथेन के साथ एकतरफा या दो तरफा कोटिड किसी भी प्रकार का टेक्सटाइल्स शामिल होता है"। पीयूसी रोल्ड फार्म या शीट फार्म अथवा किसी अन्य रूप में हो सकता है। पीयूसी को व्यावसायिक रूप से पीयू लेदर के रूप में जाना जाता है। पीयू लेदर को बाजार शब्दावली में विभिन्न नामों से भी बेचा जाता है जैसे आर्टिफिशियल पीयू लेदर, पीयू कोटिड फैब्रिक (प्लेन/प्रिंटेड/एम्ब्रोस्ड), लाइनिंग मैटिरियल, सिंथेटिक लेदर क्लॉथ, पीयू सिंथेटिक लेदर, सिंथेटिक लेदर लाइनिंग, डिपिंग पीयू लाइनिंग आदि। ऐसे सभी उत्पादों को भी पीयूसी के क्षेत्र में शामिल किया गया है। पीयूसी का बहुत से अनुप्रयोगों और क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है जैसे फर्निशिंग, ऑटोमोटिव, फुटवियर, क्लोथिंग, बैग और वालेट।
4. पीयूसी का उत्पादन प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए विनिर्माण किया जाता है जिसमें ये शामिल हैं (i) जमी हुई या गीली प्रक्रिया और (ii) ट्रांसफर कोटिंग की शुष्क प्रक्रिया। जमी हुई प्रक्रिया मुख्य प्रक्रिया है जिसका पीयूसी के विनिर्माण में ट्रांसफर कोटिंग नाम की फिनिशिंग प्रक्रिया द्वारा अनुसरण किया जाता है। इसलिए, कोई हस्ती जो इन दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ लागू नहीं करती बल्कि केवल ट्रांसफर कोटिंग प्रक्रिया को लागू करती है, को पीयूसी का विनिर्माता नहीं कहा जा सकता।
5. पीयूसी लेदर को मुख्य रूप से क्रमशः टैरिफ मद सं. 5603.94.00 और 5903.20.90 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 56 और अध्याय 59 के तहत आयातित किया जाता है। पीयूसी के आयात का कुछ अन्य विशिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षों के अंतर्गत भी अवलोकन किया गया है जैसे 3921.13.90, 5903.10.10, 5903.10.90, 5903.20.10, 5903.90.10, 5903.90.20, 5903.90.90, 5603.11.00, 5603.12.00, 5603.13.00, 5603.14.00, 5603.91.00, 5603.92.00, 5603.93.00, आदि।

समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यात किये गये और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद आवश्यक उत्पाद इन वस्तुओं की विशेषताओं जैसे भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, निर्माण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर करते हैं। इसके अलावा आवेदक ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी रूप से और व्यापारिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस कारण से इन्हें नियमावली के अंतर्गत समान वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए। इस कारण से, वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में आवेदक द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात की जा रही विचाराधीन उत्पाद के "समान वस्तु" के रूप में माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और स्थिति

7. आवेदक की उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अनुसार, भारत में पीयू लेदर के तीन उत्पादक हैं अर्थात् (i) टॉपलाइन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, (ii) जैश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मयूर यूनोकोटर्स लिमि.। आवेदक भारत में पीयू लेदर के कुल उत्पादन का 66% धारित करते हैं। अतः आवेदक नियम 2(ख) की आवश्यकता के अनुसरण में भारत में पीयूसी के कुल उत्पादन में प्रमुख समानुपात के लिए धारित करते हैं। इसके अलावा, ये नियम 5(3) की अनिवार्यता भी करते हैं क्योंकि भारत में पीयूसी के सभी प्रमुख भारतीय उत्पादक इस याचिका का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए, आवेदक इस याचिका को दायर करने के लिए स्थिति की अनिवार्यता को पूरा करते हैं और नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के अनुसरण में पीयूसी के लिए भारत में 'घरेलू उद्योग' है।

संबद्ध देश

8. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

जांच की अवधि

9. वर्तमान जांच में जांच की अवधि (जिसे यहां “पीओआई” भी कहा गया है)। अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2020 है। जांच की अवधि 12 महीने की सामान्य अवधि के स्थान पर 18 महीने ली गई है क्योंकि पीओआई जांच की शुरुआत की तारीख से 6 महीने के भीतर है। इसके अलावा, चूंकि, आवेदक ने पीयूसी का व्यावसायिक उत्पादन जून, 2017 में ही आरंभ किया है, क्षति जांच अवधि वर्ष 2017-18, 2018-19 और पीओआई को शामिल करने के लिए विचारित की गई है।

कथित पाटन का आधार**सामान्य मूल्य**

10. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ-7 की शर्तों में निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदकों ने दावा किया है कि क्योंकि उसके पास संबद्ध देश में पीयूसी की कीमत के संबंध में कोई सूचना नहीं है, आवेदक ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभों को जोड़ने के पश्चात, भारत में उत्पादन की लागत पर विचार करने के द्वारा भारत में वास्तव में अदायगी योग्य कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है और इस स्तर पर इसे ही सही माना गया है। आवेदक द्वारा दावा किए गए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य के पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं।

निर्यात कीमत

11. प्राधिकारी ने वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के सौदा-वार आयात डाटा के आधार पर संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत का परिकलन किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, अन्तर्देशीय माल भाड़ा और नॉन-रिफंडेबल वैट के लिए कीमत समायोजन किया गया है। आवेदक द्वारा दावा किए गए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात कीमत के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

पाटन मार्जिन

12. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में बहुत अधिक है। इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

क्षति और कारणात्मक संबंध का साक्ष्य

13. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कीमत ह्रासकारी और कीमत कमबिक्री प्रभाव के परिणामस्वरूप कथित पाटन के कारण हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि इसके कार्य निष्पादन पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के फलस्वरूप खोये हुए बाजार हिस्से, कम क्षमता का उपयोग, संचित मालसूची और उसके परिणामस्वरूप लाभ, नकद लाभ में गिरावट और लगाई गई पूंजी पर लाभ में गिरावट के संबंध में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

14. घरेलू उद्योग द्वारा अथवा इसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन के मौजूद होने, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की

सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, का निर्धारण करने के लिए जांच की शुरुआत करते हैं।

प्रक्रिया

15. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच के लिए पालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

16. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्र ई-मेल पते adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd11-dgtr@gov.in तथा jd14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
17. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित रूप में अथवा तरीके से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित रूप में और तरीके से उपर्युक्त पैरा 18 में उल्लिखित इमेल पते पर इस जांच से संगत अपने अनुरोध भी प्रस्तुत कर सकता है।
19. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय सीमा

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना के प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उपर्युक्त ई-मेल पते adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd11-dgtr@gov.in तथा jd14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। हालांकि, यह नोट किया जाये कि उक्त उप-नियम की व्याख्या के संबंध में, सूचना और अन्य दस्तावेजों को मंगाने वाले नोटिस के संबंध में यह माना जायेगा कि वह उस तिथि से एक सप्ताह पहले प्राप्त हो गया है जिस तिथि को इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश से उपर्युक्त राजनयिक प्रतिनिधि को भेजा गया था अथवा संप्रेषित किया गया था। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना पूरी नहीं हो तब प्राधिकारी इस नियमावली के अनुसार रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को रिकार्ड कर सकते हैं।
21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचना दें और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/ अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
23. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्टों/ अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों से यह अपेक्षित है कि वे पृथक रूप से गोपनीय और अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करें।
24. “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” के रूप में स्पष्ट से चिह्नित किया जाना चाहिए। ऐसे चिह्न के बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उन अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
25. गोपनीय पाठ में वे सभी सूचना निहित होंगी जो गोपनीय प्रकृति की हैं और/ अथवा अन्य प्रकार की सूचना हैं जो इस प्रकार की सूचना देने वाले व्यक्ति गोपनीय के रूप में दावा करते हैं। उस सूचना के लिए, जिसके संबंध में

गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा वह सूचना जिसके संबंध में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचना देने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ-साथ सही कारण का विवरण उपलब्ध कराएं कि क्यों इस प्रकार की सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

26. अगोपनीय पाठ के लिए यह अपेक्षित है कि वह गोपनीय सूचना अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा कवर किया (यदि अनुक्रमण संभव नहीं हो) और उस सूचना जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया हो, के आधार पर सारांश किए जाने के साथ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति हो। अगोपनीय सारांश विस्तृत व्यौरे के साथ होने चाहिए जिसमें कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के अर्थ को तर्कसंगत तरीके से समझा जा सके। हालांकि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि क्यों इसका सारांश किया जाना संभव नहीं है।
27. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाला व्यक्ति इस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं है अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में इसके प्रकटन के लिए अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तब प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
28. उसके सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में सही कारण का विवरण दिए बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
29. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

30. इस नियमावली के नियम 6(7) के संबंध में, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। सार्वजनिक फाइल को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखने के तौर तरीकों का निर्धारण किया जा रहा है।

असहयोग

31. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना तक पहुंच की अनुमति देने से इंकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाता है तब प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें, जिसे वे उचित मानते हों, कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2021

Case No. AD-OI-46/2020

Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Polyurethane Leather which includes any kind of textile coated one sided or both sided with Polyurethane” originating in or exported from China PR.

No. 6/55/2020-DGTR.—M/s. Topline Commodities Private Limited (hereinafter also referred to as the “Applicant”) has filed an application (hereinafter also referred to as the “Petition”) seeking initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Polyurethane Leather which includes any kind of textile coated one sided or both sided with Polyurethane”, (hereinafter also referred to as “subject goods” or the

“product under consideration”) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as “subject country”) before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”).

2. The Applicant has alleged that material injury to the domestic industry is being caused due to dumped imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country and has requested for imposition of the anti-dumping duty on the import of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Product Under Consideration

3. The product under consideration (PUC) is “Polyurethane Leather which includes any kind of textile coated one sided or both sided with Polyurethane”. PUC may be in rolled form or sheet form or any other form. The PUC is commercially known as PU Leather. PU Leather is also sold in market parlance by various names such as artificial PU Leather, PU Coated Fabric (Plain/ Printed/ Embossed)/, Lining Material, Synthetic Leather Cloth, PU Synthetic Leather, Synthetic Leather Lining, Dipping PU Lining etc. All such products are also included within the scope of the PUC. The PUC is used in many applications and sectors, such as furnishing, automotive, footwear, clothing, bags and wallets.

4. PUC is manufactured using the production process which comprises (i) the coagulation or wet process and (ii) the transfer coating or dry process. The coagulation process is the key process which is followed by the finishing process called transfer coating in the manufacturing of PUC. Therefore, any entity which does not carry out both these processes together but merely carries out the transfer coating process cannot be said to be a manufacturer of PUC.

5. PU Leather is primarily imported under Chapter 56 and Chapter 59 of the Customs Tariff Act, 1975 under tariff items 5603.94.00 and 5903.20.90 respectively. The imports of PUC are also observed under certain other customs tariff headings viz. 3921.13.90, 5903.10.10, 5903.10.90, 5903.20.10, 5903.90.10, 5903.90.20, 5903.90.90, 5603.11.00, 5603.12.00, 5603.13.00, 5603.14.00, 5603.91.00, 5603.92.00, 5603.93.00, etc.

Like Article

6. The Applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject country and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and product under consideration imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The Applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as 'Like Article' to the product under consideration being imported from the subject countries.

Domestic Industry and Standing

7. As per the best information available to the Applicant, there are three producers of PU Leather in India, namely, (i) Topline Commodities Private Limited, (ii) Jasch Industries Limited and Mayur Uniquoters Limited. The Applicant holds 66% of the total production of PU Leather in India. Thus, the Applicant holds major proportion in total production of the PUC in India in line with the requirement of Rule 2(b). Furthermore, the requirement of Rule 5(3) is also fulfilled as all major Indian producers of PUC in India are supporting this petition. Therefore, the Applicant satisfies the requirement of standing for filing this petition and constitutes ‘domestic industry’ in India for PUC in accordance with Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Rules.

Subject Country

8. The subject country for this investigation is China PR.

Period of Investigation

9. The Period of Investigation (hereinafter also referred to as “POI”) in the present investigation is 1st April, 2019 to 30th September, 2020. The period of investigation is taken as 18 months instead of normal period of 12 months so that the POI is within 6 months from the date of initiation. Further, since the Applicant has started the commercial production of the PUC only in June 2017, the injury investigation period has been considered to include the years 2017-18, 2018-19 and the POI.

Basis of Alleged Dumping**Normal value**

10. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The Applicant claims that as it did not have any information with respect to the price of the PUC in the subject country, the Applicant has constructed the normal value on the basis of the price actually payable in India by considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits and the same has been considered appropriate at this stage. There is sufficient prima facie evidence of the normal value for subject goods from the subject country claimed by the Applicant.

Export Price

11. The Authority has computed the export price for the subject country based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight and non-refundable VAT. There is sufficient prima facie evidence of the export price for subject goods from the subject country claimed by the Applicant.

Dumping Margin

12. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin is above the de-minimis level and significant in respect of the product under consideration from the subject country. There is prima facie evidence that the product under consideration from subject country is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

Evidence of Injury and Causal Link

13. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished prima facie evidence regarding the injury as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price suppression, price depression and price underselling. The Applicant has claimed that its performance has been adversely impacted in respect of lost market share, low capacity utilisation, accumulated inventories and consequent decline in profits, cash profits and decline in return on capital employed, as a result of increase in imports of product under consideration. There is sufficient prima facie evidence that the injury is being caused to the domestic industry by dumped imports of the subject goods from subject country.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

14. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Procedure

15. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of Information

16. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Authority via email at the email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd11-dgtr@gov.in and jd14-dgtr@gov.in.

17. The known producers/exporters in the subject country, its governments through its embassy in India, the importers and users in India known to be connected with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set below.

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within in the time limit set out below.

19. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to other interested parties.

Time Limit

20. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd11-dgtr@gov.in, and jd14-dgtr@gov.in. within 30 days from the date of the receipt of the notice as per rule 6 (4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rules, the notice calling for information and other documents shall be deemed to be have been received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.

21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

22. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

23. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto) before the Authority, including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

24. The “Confidential” or “Non-confidential” submissions must be clearly marked as “Confidential” or “Non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be a liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

25. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

29. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

30. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Non-cooperation

31. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority